



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में कोविड-19 महामारी के समाधान के लिए सरकारी प्रयास :

एक सामाजिक, राजनैतिक वि"लेषण

डॉ. राजेश कुमार त्रिपाठी

असि. प्रोफे.-समाज"ास्त्र

गोविंद बल्लभ पंत पी.जी. महाविद्यालय, कछला (बदायूँ)

सम्बद्ध : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड, वि.वि. बरेली (उ.प्र.)

मुख्य शब्दावली : कोविड, वायरस, महामारी, वोरवेल नीति

सारांश : कोविड वायरस से पीड़ित पहले मामले की पुष्टि चीन के हुबेई प्रांत के बुहान शहर में दिसम्बर 2019 में हुई। जिसकी बढ़ती संक्रमकता की दर के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया। यह पृथ्वी पर मानव सभ्यता के आर्विभाव के प"चात् की सबसे भीषण त्रासदी थी। भारत सहित दुनिया भर के दे"ों ने इससे निपटने के लिये सरकारी स्तर पर अपने-अपने ढंग से कई प्रयास किये। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने उक्त महामारी से निपटने के लिये भारत सरकार के द्वारा किए गये भिन्न प्रयासों का एक सामाजिक, राजनैतिक वि"लेषण का प्रयास किया है। जो भविष्य के शोधकर्ताओं के लिये शोधार्थी की सामाजिक, आर्थिक एवं वैषयिक सीमाओं के विस्तार के साथ उपयोगी साबित हो सकता है।

भूमिका : कोविड-19 महामारी के फैलने के चलते उत्पादन आवागमन, व्यापार, बाजार एवं सभी क्षेत्रों में जहाँ एक तरफ मन्दी के कारण करोड़ों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। दुनिया भर की सरकारों से जन अपेक्षाएँ ज्यादा थीं। भारतीय समाज भी भारत सरकार से इस महामारी से निपटने के लिये एक सार्थक प्रयास की उम्मीद कर रहा था। जहाँ हम आशा और अपेक्षा कर रहे थे कि मनुष्य इतिहास से सबक लेकर इस महामारी से निपटने के लिये साझेपन की कोई सोच विकसित कर सकेगा लेकिन असलियत यह थी कि पहले से चली आ रही दरारें, विषमताएँ और विखराव को भारत सरकार के तंत्र ने भी इस दौरान आंशिक स्तर पर उसे बढ़ाया यद्यपि वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से महामारी को नियन्त्रित करने का भी प्रयास किया।

साहित्य सर्वेक्षण : शोधार्थी ने अपने शोध कार्य को व्यापकता एवं विश्वसनीयता प्रदान करने लिये निम्न पुस्तकों के अध्ययन द्वारा शोध समस्या का सामाजिक, राजनैतिक वि"लेषण का प्रयास किया है :-

1. एनालिटिकल सोशियोलॉजी 1955 — लेखक कार. लॉवेल जे.
2. द मेडिसिन एण्ड द राज 1998 लेखक — अनिल कुमार (इतिहासकार)
3. द कोरोना वॉयरस लेखक — स्वपनिल पारिख, माहिरा दे"आई एवं अन्य
4. द रेसिकल डिस्क्रिप्शन"न इन द कांटेक्सट आफ द कोविड-19 क्राइसेस-2020

शोध पविधि एवं अध्ययन क्षेत्र :-

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने कोविड-19 महामारी के समाधान के लिये भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रयासों का सामाजिक, राजनैतिक विश्लेषण करने के लिये वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना का प्रयोग करेगा।

समस्या कथन :- "कोविड-19 महामारी के समाधान के लिये सरकारी प्रयास : एक सामाजिक, राजनैतिक वि"लेषण"

शोध समस्या :- कोविड-19 के दौरान भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रयासों की वास्तविकता

अध्ययन उद्देश्य :- कोविड-19 महामारी की रोकथाम में सरकारी तंत्र के प्रयासों की वास्तविकता का पता लगाना।

प्राक्ल्पना :- प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निम्न प्राक्ल्पना प्रस्तावित की गयी -

1. भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रयास भारतीय समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरे।
2. भारत सरकार के द्वारा सरकारी तंत्र के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान समाज के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास किया।

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन की सुविधा एवं उपलब्ध संसाधनों तथा शोधार्थी की वैषयिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुये शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद को शोध स्थल के रूप में चुना गया है।

अध्ययन क्षेत्र परिचय : अम्बेडकर नगर जनपद का निर्माण 29 सितम्बर 1995 को हुआ। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार यहाँ कुल जनसंख्या-2397888 है। यह जिला 2520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ कुल 9 प्रशासनिक विकास खण्ड हैं। इस जनपद की साक्षरता दर 74.37% और लिंगानुपात 976 है। उक्त स्थल को शोध स्थल के रूप में चुने जाने का कारण बहुलवादी सामाजिक जनसंख्या है।

समग्र :- इसके अन्तर्गत अम्बेडकर नगर जनपद के टांडा नामक विकास खण्ड के ग्राम भारीडीहा की साक्षर जनसंख्या जो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार लगभग 5000 है।

निदर्श :- प्रस्तुत शोध में निर्देश के रूप में 100 उत्तरदाताओं का निदर्शन की उपयुक्त विधि के माध्यम से चयन किया गया है। जो समग्र का 0.02% है।

निदर्शन को स्पष्ट करते हुये पी.वी.यंग. कहते हैं कि "एक सांख्यिकीय निदर्शन सम्पूर्ण समूह का लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है" *1

तथ्य संकलन के स्रोत : शोधार्थी के द्वारा उक्त अनुसंधान को मूर्त रूप देने के लिये सूचना के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को शामिल किया है। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं, प्रमाणित शोध ग्रंथ, वेबसाइटों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि : किसी भी अनुसंधान की प्राक्ल्पना की जाँच के लिये तथ्यों का संकलन महत्वपूर्ण होता है। जोकि प्रस्तुत शोध में प्राथमिक शोध के रूप में साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा तथा द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किया गया है। ऐसे में उत्तरदाता की पृष्ठभूमि जानना महत्वपूर्ण होता है।

"जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों द्वारा होता है।" *2

दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट करते हुये “कार्य कारण सम्बन्ध एवं वस्तुनिष्ठता” को महत्वपूर्ण माना *3

प्रस्तुत शोध में अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण जनसंख्या की पृष्ठभूमि से हैं जिसमें हिन्दू (SC/ST/OBC) जनसंख्या तथा मुस्लिम आबादी भी है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध में उत्तरदाता एक बहुलबादी सामाजिक संरचना वाली जनसंख्या से हैं।

प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या : प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन दैवनिर्दर्शन एवं सुविधापूर्ण दैवनिर्दर्शन विधि के माध्यम से ग्राम भारीडीहा (विकास खण्ड टांडा, जनपद अम्बेडकर नगर) से किया गया है।

उपरोक्त उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को सारणी के द्वारा प्रस्तुत करते हुये साक्षात्कार अनुसूची के प्र”नों का विश्लेषण किया जायेगा—

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न-1

कोविड महामारी के दौरान सरकार तंत्र के प्रयास से आप सहमत हैं— हाँ/नहीं

साक्षात्कार अनुसूची के उपरोक्त प्र”न पर शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया कि 100 उत्तरदाताओं ने निम्न रूप में प्रतिक्रिया दिया—

(सारणी नं.-1)

क्रमांक	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रति”त
1	हाँ	40	40%
2	नहीं	50	50%
3	मालूम नहीं	10	10%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाताओं में से 40 प्रति”त उत्तरदाताओं में सरकार के प्रयास के प्रति सहमति व्यक्त की जबकि वहीं दूसरी तरफ 50 प्रति”त उत्तरदाता सरकार के द्वारा किये गये प्रयासों से असंतुष्टि दर्शायी जबकि 10 प्रतिशत ने कहा कि कुछ मालूम नहीं। इससे स्पष्ट है कि अधिकां”त उत्तरदाता सरकार के द्वारा किये गये प्रयासों से संतुष्ट नहीं थे।

(सारणी नं.-2)

क्रमांक	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रति”त
1	हाँ	35	35%
2	नहीं	55	55%
3	मालूम नहीं	10	10%

साक्षात्कार अनुसूची प्रश्न-2

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार के प्रयास विभाजनकारी थे — हाँ/नहीं

साक्षात्कार अनुसूची के उपरोक्त प्र”न पर शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया कि 100 उत्तरदाताओं ने निम्न रूप में प्रतिक्रिया दिया—

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाताओं में से 35 प्रतिशत ने यह माना कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी स्तर पर विभाजनकारी प्रयास किया गया जबकि 55 प्रति”त उत्तरदाताओं ने इससे इंकार किया वहीं 10 प्रति”त इस संदर्भ में मौन रहे। उपरोक्त सारणी से स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भले

ही सीमित स्तर पर लेकिन सरकारी भेदभाव समाज के एक वर्ग वि"ष के प्रति दृष्टिगत हुआ है जो सरकार की मं"ा पर सवाल खड़ा करता है।

द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह पता चलता है कि सरकार के द्वारा पूर्व में चलायी जा रही "समावे"ी विकास के लिये मेक इन इंडिया स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडप इंडिया जैसी योजनायें जो भारत सरकार के सामाजिक, आर्थिक विकास की गति को सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण साबित होती।" *4 इन योजनाओं को कोविड-19 के दौरान वि"ष रूप से गति प्रदान की गयी।

लाकडाउन के दौरान भारत सरकार ने 32 करोड़ से अधिक जनधन खातों में 500 रुपये प्रति माह डालने का निर्णय लिया। वहीं खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में 2/3 आबादी को नि:शुल्क 35 किलोग्राम अनाज नि:शुल्क प्रदान किया गया। कोविड के दौरान सरकार का यह प्रयास बी.पी.एल. आबादी के लिये संजीवनी बूटी से कम नहीं था जो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के समाज के सभी गरीब वर्गों के लिये था। इस दौरान सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी पर प्रभाव"ाली नियंत्रण स्थापित करने के लिये कई अन्य प्रयास किये गये जैसे-लाकडाउन, क्वरंटाइन की व्यवस्था, अरोग्य सेतुएप, अस्पतालों में कोविड वार्ड का निर्माण, अप्रवासी भारतीयों को भारत में लाने के लिये वंदे भारत मिशन इसके साथ स्थानीय स्तर पर कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन तथा कोविड हैल्पलाइन नंबर एवं जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये। बाद में प्रभावी नियंत्रण के लिये दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम जिसके द्वारा देश की सम्पूर्ण आबादी को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के टीकाकरण किया गया।

निष्कर्ष : उपरोक्त प्रदत्तों के वि"लेषण से स्पष्ट है कि शोधार्थी के द्वारा जो प्राक्ल्पनायें प्रस्तावित की गई थीं उनमें से दोनों प्राक्ल्पनायें असत्य साबित हुईं अर्थात् शून्य परिकल्पना साबित हुईं। इससे स्पष्ट है कि आज भी भारतीय समाज का एक सीमित वर्ग सरकार की नीतियों को लेकर संदेह व्यक्त करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के द्वारा किये गये प्रयास महत्वपूर्ण थे यद्यपि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये यह चुनौतीपूर्ण था।

कोविड-19 में मानव जीवन की कई विद्रूपताओं को उजागर किया जिसका भविष्य में समाज की संस्थाओं पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

संदर्भग्रंथ सूची :

1. यंग पी.वी. : साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च 1971 –पेज नं. 325
2. प्येनकेयर हेनरी : साइंस एण्ड मेथड, 30 नवम्बर 2011 –डोवर पब्लिकेशन
3. दुर्खीम इमाइल: रूल्स ऑफ सोसियोलॉजिकल मेथड –1895 पेरी लिवरारी फेलिक्स एल्कान पब्लिकेशन
4. महापात्र एन. के.: सैनित्वा (स्वच्छ भारत मिशन) –गवर्नमेंट एण्ड सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट इन इंडिया
– यूरोपियन साइंटिफिक जर्नल
विशेष अंक
पृष्ठ संख्या–170–177 वर्ष 2015

